अवध की आवाज

www.avadhkaawaz.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष–12 अंक–104 R.N.I.- UPHIN/2012/45127 लखनऊ गुरुवार 15 अगस्त 2024 पृष्ठ – 4 मूल्य–3 रुपया

संक्षिप्त समाचार

यूपी उपचुनाव में दो सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी निषाद पार्टीरू संजय निषाद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले यूपी में एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ गई हैं। दरअसल, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने उपचुनाव को लेकर बड़ा बड़ा ऐलान किया है। निषाद ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी मझवा और कटेहरी से विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ेगी। दरअसल, संजय निषाद 16 अगस्त को निषाद पार्टी की स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान यह बात की है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेगी। आप को बता दें कि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर अब विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीख को के ऐलान से पहले संजय निषाद ने एक बड़ा ऐलान कर अपना रुख साफ कर दिया है। संजय निषाद ने मझवां और कटेहरी की सीट पर अपने सिंबल पर चुनकव लड़ाने का ऐलान किया है। हालांकि संजय निषाद ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं और इन सीटों पर हम इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं जिसमें से एक सीट जीते थे। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी क्या भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में से अपने सहयोगियों को कितनी सीट देगी। इसे लेकर पार्टी ने अभी कोई भी ऐलान नहीं किया है।

भाजपाइयों ने उड़ाई यातायात नियमों की धज्जियां, बिना हेलमेट के तिरंगा यात्रा में दौड़ाते रहे बाइक

उरई/जालौन। जालौन में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। मगर इस तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता यातायात नियमों की खुले आम धज्जियां उड़ते नजर आए। जहां भाजपाई बिना हेलमेट के ही बाइकों पर फर्राटा भरते नजर आए। इतना ही नहीं भाजपाई बाइक पर स्टंट भी करते हुए नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले मूक दर्शक बने खड़े रहे। लेकिन उन्होंने किसी भी भाजपा पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। भाजपा ने उरई के टाउन हॉल से शहर के विभिन्न चौराहों से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों के साथ–साथ समाज सेवियों ने प्रतिभाग किया था। मगर सत्ता के मध में चूर भाजपा कार्यकर्ता खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। बाइकों से निकली गई तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता बिना हेलमेट के ही बाइक पर फर्राटा भरते नजर आए। इस दौरान बाइक पर पीछे बैठने वाले लोग स्टंट करते नजर भी आए। भाजपा कार्यकर्ता बार–बार चलती हुई बाइकों पर खड़े होकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। वहीं पुलिस वाले भी भाजपा कार्यकर्ताओं के इस कारनामे को देखते हुए मूक दर्शक बने खड़े रहे। उन्होंने किसी भी भाजपा कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से मना नहीं किया। वह सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं के इस तमाशे को देखते रहे।

भाजपा में हलचल के बीच पीएम से मिले डिप्टी सीएम,हुई यूपी के हालात पर चर्चा

लखनऊ। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में लगातार अंदरुनी कलह की बात सामने आ रही थी। आरोप–प्रत्यारोप का दौर चला।हार की समीक्षा के लिए मंथन खूब हुआ। बवाल तब बढ़ा जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ये कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है।अब इसी विवाद को लेकर एक नई खबर है। तीन दिन पहले केशव मौर्य की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। सूत्रों के मुताबिक केशव मौर्य ने पीएम मोदी को यूपी में बीजेपी का हालात की जानकारी दी है।केशव मौर्य ने पीएम को लोकसभा चुनाव में हार की वजहें भी बताई।सूत्रों का दावा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 11 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।सूत्रों के मुताबिक केशव ने पीएम को यूपी के हालातों की जानकारी दी।लोकसभा में यूपी में बीजेपी के हार के कारणों की जानकारी दी।इससे पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पीएम से मिल चुके हैं।भूपेंद्र चौधरी ने भी पीएम को दी थी यूपी की जमीनी स्थिति और हार के कारणों की जानकारी दी थी।संसद सत्र के दौरान यूपी से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी और सहयोगी दल के कई नेताओं ने पीएम से मुलाकात की और यूपी की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इनमें पूर्व सांसद संजीव बालयान, साध्वी निरंजन ज्योति व अपना दल की नेता, मीरजापुर सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हैं।अपना दल की नेता ने लोकसभा चुनाव के बाद ही आरक्षण के मुद्दे पर चिट्ठी भी लिखी थी जिस पर काफी सियासत हुई। इसी मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी चिट्ठी लिखी थी।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, मौन पदयात्रा में शामिल हुए योगी,देखी प्रदर्शनी

विभाजन की त्रासदी दोबारा नहीं दोहराने देंगे : योगी

विभाजन का दर्द अनकहा, कई दिलों ने था यह सहा

लखनऊ। विभाजन विभीषिका स्मृति की मौन पद यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शनी भी देखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को लखनऊ में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की मौन पदयात्रा में शामिल हुए। विभाजन में अपनी जान गंवाने और भीषण पीड़ा का सामना करने वालों को याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले सरकार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर लोकभवन तक मौन पदयात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभाजन को लेकर लिखे संदेश की तख्ती भी अपने हाथ में ले रखी थी, जिसपर लिखा था कि विभाजन का दर्द अनकहा, कई दिलों ने था यह सहा।इस मौन यात्रा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्यसभा सदस्य व पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा भी शामिल हुए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर मौन पदयात्रा पर निकले।केंद्र में भाजपा की सत्ता आने के बाद से स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन विभाजन की स्मृतियों को याद किया जाता है। 14 अगस्त की वह घड़ी... दिलों में आज भी बनाती है घाव की लड़ी... ।ये पंक्तियां विभाजन की यादों को ताजा करती हैं।दिलों में आग थी, आंखों में पानी। भारत ने देखी थी ये दर्द भरी कहानी। इस तरह की लाइनें लिखी तख्ती लेकर सभी माननीय मौन पदयात्रा में शामिल हुए और शोक जताया। इस मौके पर लोकभवन में प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें विभाजन की स्मृतियों को संजोया गया था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगे के साथ सेल्फी भी ली। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमें अपनी उन गलतियों से सीखना होगा, जिसे ढाल बनाकर विदेश आक्रमणकारी देश में घुसे और उन्होंने हमारे पवित्र तीर्थ स्थलों को तोड़ा। उन्होंने भारत की अखंडता और संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की। विभाजन की त्रासदी को हम दोबारा नहीं दोहराने देंगे। हमें राष्ट्र प्रथम की तर्ज पर चलना होगा।सीएम योगी ने आगे कहा कि डेढ़ करोड़ हिंदू आज बांग्लादेश के अंदर चिल्ला–चिल्लाकर अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं लेकिन दुनिया बिल्कुल चुप है। 1947 में कई लोगों ने विभाजन की त्रासदी झेली। पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं है। पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए इतिहास से समाप्त हो जाएगा।

नवयुग कन्या महाविद्यालय में सावन मेला का आयोजन

लखनऊ। नवयुग कन्या महाविद्यालय की भारतीय भाषा, संस्कृति और कला समिति द्वारा सावन मेला का आयोजन किया गयाइस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री एवं समाज सेविका अपर्णा यादव और विशिष्ट अतिथि शिवाशक्ति फाउंडेशन की अध्यक्ष पुनीता भटनागर उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से की गई। अतिथियों का स्वागत पौधा, अंगवस्त्र से किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो मंजुला उपाध्याय ने अथितियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय परम्परा को निखारने और संजोए रखने के लिए इस तरह के उत्सव होने चाहिए। हमारी संस्कृति जो जीवन में परिवार, रिश्ते, नातेदार, भावना और मानवीय सम्बंधा के महत्व को समझती है, इसलिए कजरी, झूला और हिंडोला जैसे त्यौहारों से इन्हें हमेशा जीवंत रखने की कोशिश करती हैं। समाज सेविका अपर्णा यादव ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि नवयुग की छात्राओं को देख कर लग रहा सावन अपने चरम पर है। उन्होंने प्राचार्या को बधाई देते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि यह महाविद्यालय लोक कलाओं को बढ़ावा दे रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जिंदगी की सीख से पहले आपको अपने अध्यापक से सीखना चाहिए, यही समय है आपके जिंदगी का इसको भरपूर जीते हुए, सीखते हुए आनंद लीजिए और अपने अंदर के बच्चे को हमेशा यूहीं बचाएं रखें। इसके साथ ही उन्होंने बहुत ही मधुर गीत बरखा ऋतु बैरी हमारे और हर घर तिरंगा अभियान को जागृत करते हुए वंदे मातरम् गाकर सभी को अपनी मधुर आवाज से मंत्रमुग्ध किया। जिससे हर घर तिरंगा अभियान का रंग सावन मेले में दोगुना हो गया। महाविद्यालय की प्राचार्या और अपर्णा यादव के कर कमलों द्वारा प्रांगण में सजे झूले का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम में उनकी संस्था 'बी अवेयर' द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। भारतीय भाषा संस्कृति और कला समिति के सदस्यों द्वारा गीत प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय की सभी छात्राओं ने सावन मेला के विभिन्न पारम्परिक कार्यक्रम में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। अंकिता लोधी और सारिका (बीए) ने पहाड़ी नृत्य, अर्शी सिद्दीकी और अनन्या शर्मा ने कजरी पर ठुमके लगाए। यशप्रिया, श्रेया और अन्य छात्राओं ने लोक गीत से लोगो को मंत्रमुग्ध किया। कुछ छात्राओं ने मेहंदी लगाने में अपनी कला दिखाई, तो कुछ ने अपनी चटपटी चाट और बताशो से सबका मन जीता। रसायन विभाग की प्रबुद्ध प्रवक्ता डॉ सुनीता सिंह और डॉ चंदन मौर्या ने भी कजरी गाकर उत्सव की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का संचालन प्रो सीमा सरकार और डा अपूर्वा अवस्थी ने किया। भारतीय भाषा संस्कृति और कला समिति की समन्वयक प्रो अमिता रानी सिंह एवं सभी सदस्य प्रो सीमा सरकार, डा आभा पाल , डा अपूर्वा अवस्थी, ललिता पांडे, और नेहा ने कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। महाविद्यालय की सभी प्रवक्ताएं और छात्राएं इसमें उपस्थित रहीं।

मां ने मोबाइल पर गेम खेलने से रोका तो बेटे ने दे दी जान

बांदा। कॉलेज जाते समय मोबाइल पर गेम खेल रहे बेटे को मां ने डांट दिया। इससे नाराज होकर उसने फंदा लगाकर जान दे दी। बदौसा थाना क्षेत्र के महुराई अंश दुबरिया गांव निवासी विकास कुमार (16) ने मंगलवार की दोपहर कमरे में पंखे से लटककर फंदा लगा लिया। ममेरे भाई ललित किशोर ने बताया कि विकास चित्रकूट इंटर कॉलेज, कर्वी में 10वीं का छात्र था। वह कर्वी में किराये पर कमरा लेकर पढ़ाई करता था। इन दिनों वह अपने घर में था। मंगलवार को उसकी मां चुनबादी ने कॉलेज के लिए बैग तैयार करने के लिए कहा और मोबाइल देखने पर डांट दिया। इसी बात से नाराज होकर उसने फंदा लगा लिया। पिता आनंद किशोर दमनदीप में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। एक बहन में वह इकलौता भाई था। बदौसा थानाध्यक्ष जयचंद्र सिंह ने बताया कि पिता आनंद किशोर दमनदीप में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। एक बहन में वह इकलौता भाई था। छात्र ने फंदा लगाया है।

भाषा विश्वविद्यालय: छात्रों ने निकाली तिरंगा रैली, शहीदों के बलिदान को किया नमन

लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विवि में रोवर्स टीम ने हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया। इसका कार्यक्रम में कुलपति प्रो.एन.बी.सिंह मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस मौके पर स्वतंत्रता के संघर्ष को याद कर इसके महत्व को उजागर किया गया और काकोरी शहीदों के वीरगाथा को 100 साल पूरे होने पर डॉ. मुन्नवर हुसैन ने छात्रों के बीच विशेष उल्लेख किया। जिसमें विश्वविद्यालय के छात–छात्रा और शिक्षक ने अपनी सहभागिता दर्ज कर शायरी व कविता पाठ और उद्बोधन के माध्यम से राष्ट्रव्यापी आभियान को सफल बनाया। कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी रोवर्स डॉ.सिद्धार्थ सुदीप ने किया था। विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. एन. बी सिंह के तत्वाधान में एनएसएस यूनिट चार और पांच द्वारा हर घर तरंगा अभियान के तहत विश्वविद्यालय प्रांगण में तिरंगा रैली निकाली। यह तिरंगा रैली एनएसएस समन्वयक डॉ. नलिनी मिश्रा, डॉ. अभय कृष्णा और डॉ. जफरुल नकी के नेतृत्व में भाषा विश्वविद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक से शुरू हुई और देशभक्ति के नारे लगाते हुए विश्वविद्यालय के एडमिन ब्लॉक पर समाप्त हुई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. महेश कुमार ने कहा कि देश का झंडा देश की पहचान है और यह देश के लोगों के लिए सबसे मूल्यवान चीज है, इसलिए इसे दिल और आत्मा से अधिक प्यार करना चाहिए। देश की सेवा करने के लिए हर दम उपस्थित रहना चाहिए और साथ ही पूर्वजों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस रैली में छात्रों को संबोधित करते हुए एनएसएस समन्वयक डॉ. नलिनी मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में इस तिरंगा रैली को निकालने का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा की जा सके और उन्हें अपने घरों पर भारतीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके है। इस तिरंगा रैली के अंतिम चरण में डॉ. अभय कृष्णा ने शिक्षकों, छात्रों और एनएस स्वयंसेवकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह झंडा हमें यूं ही नहीं मिला, इसके लिए बलिदानों की एक लंबी शृंखला है, इसकी रक्षा करना और इसका आदर और सम्मान करना हम सब के न केवल जरूरी है बल्कि एक देशभक्त के लिए यह जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तिरंगा रैली में विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉ. नीरज शुक्ल और अन्य शिक्षकों के साथ–साथ छात्र और एन.एस.एस. स्वयंसेवक शामिल हुए।

कोलकाता की घटना के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी

लखनऊ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के विरोध में उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों ने लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन किया। किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के 200 से अधिक जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार को विश्वविद्यालय से स्वास्थ्य महानिदेशालय तक जुलूस निकाला। सभी रेजिडेंट हाथों में पोस्टर लिए हुए थे और नारे लगा रहे थे। जुलूस में शामिल लोगों में महिला चिकित्सकों की संख्या काफी अधिक थी। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा दिये जाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश 'रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन' (आरडीए) के अध्यक्ष डॉ. हरदीप जोगी ने बताया कि कोलकाता में एक डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के विरोध में प्रदेश में ग्रेटर नोएडा से लेकर वाराणसी और कानपुर, झांसी, आगरा, गोरखपुर जैसे शहरों के अलावा राजधानी लखनऊ में भी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में लगातार तीसरे दिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों ने प्रदर्शन में भाग लिया, उनमें आपातकालीन सेवाएं जारी है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में शुक्रवार की सुबह एक महिला चिकित्सक का शव मिला था और इस घटना के सिलसिले में शनिवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। डॉ. हरदीप जोगी ने कहा कि इस घटना से परिसर की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही का पता चलता है। उन्होंने कहा, "आरडीए उत्तर प्रदेश इस युवती की मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। यह घटना हमारे संस्थानों की सुरक्षा करने में प्रशासन और शासन की गंभीर चूक को दर्शाती है। आरडीए ने चिकित्सा समुदाय के सामने आने वाले ज्वलंत मुद्दों, डॉक्टरों के खिलाफ "बढ़ती हिंसा" और "बिगड़ती कार्य स्थितियों" पर चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के साथ तत्काल एक बैठक की भी मांग की। उन्होंने कहा, "भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।" डॉक्टरों के संघ ने चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई उपाय सुझाये हैं, जिनमें पर्याप्त संख्या में पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना शामिल है।

उपायुक्त और बीडीओ समेत 10 अधिकारियों पर धोखाधड़ी का केस

बांदा। मृतक महिला का फर्जी मस्टररोल बनाने और मनरेगा योजना के तहत सरकारी धन हड़पने के मामले में सीजेएम भगवानदास गुप्ता की अदालत ने तत्कालीन उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा और बीडीओ नरैनी समेत 10 अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। धारा 156–3 के तहत सीजेएम न्यायालय में आवेदन किया गया था। शहर के सिविल लाइन निवासी लल्लू सिंह पुत्र वीर सिंह ने सीजेएम की अदालत में 156–3 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया था। बताया था कि ग्राम पंचायत बिल्हरका विकास खंड नरैनी की श्रमिक माया पत्नी रज्जू का जाब कार्ड नंबर यूपी42–008–012–004/82 था। श्रमिक माया पत्नी रज्जू की मृत्यु 28 दिसंबर 2016 को हो चुकी है। माया की मृत्यु हो जाने के बाद मनरेगा योजना का सरकारी धन हड़प करने के उद्देश्य से तत्कालीन उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा राघवेंद्र तिवारी वर्तमान तैनाती महोबा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग खंड–1 डीएस यादव, अवर अभियंता बीके सिंह, तत्कालीन बीडीओ कार्यक्रम मनरेगा विकासखंड नरैनी मनोज कुमार, वर्तमान तैनाती जनपद प्रयागराज, तत्कालीन बीडीओ नरैनी प्रकाश प्रसाद वर्तमान तैनाती ब्लाक तिंदवारी, ग्राम रोजगार सेवक बबलू बिल्हरका, नागेंद्र प्रसाद दीक्षित लेखाकार विकासखंड नरैनी वर्तमान तैनाती ग्राम पंचायत नहरी, रमाकांत धुरिया तत्कालीन लेखाकार मनरेगा ब्लाक नरैनी, विनय सिंह तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास खंड बिल्हरका वर्तमान तैनाती नहरी, प्रमोद कुमार कंप्यूटर आपरेटर ब्लाक नरैनी आदि ने मृतक महिला श्रमिक के नाम मस्टर रोल संख्या–14307 कार्य की अवधि 1 दिसंबर 2020 से लेकर 16 दिसंबर 2020 के जाब कार्ड दिखाकर धोखाधड़ी करते हुए धन हड़प कर लिया। इसी प्रकार छल कपट, बेईमानी से सरकारी धन हड़प करने के आशय से उक्त श्रमिक माया के नाम 2020–21 के मस्टर रोल 7106, 7806, 9229 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के मस्टर रोल 3168, 3582 उक्त सभी अधिकारियों ने आपस में आपराधिक षड़यंत्र रचकर मृतक श्रमिक माया के नाम की धनराशि हड़पी गई। सीजेएम न्यायालय ने सभी अधिकारियों के खिलाफ कोतवाली नरैनी में रिपोर्ट दर्ज करने और विवेचना के निर्देश दिए हैं। साथ ही रिपोर्ट दर्ज करते हुए एग प्रति न्यायालय को भेजने का आदेश भी सीजेएम की अदालत ने दिया है।

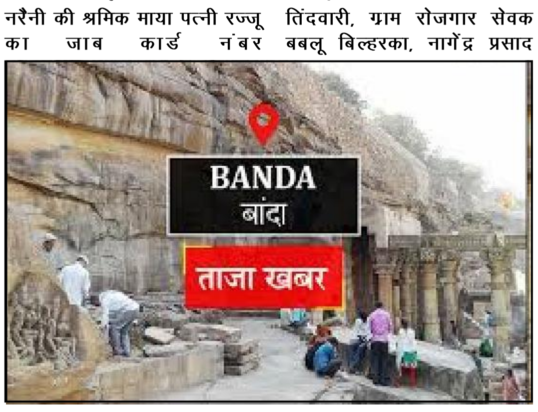

सम्पादकीय

विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के हनन का सवाल

जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ कहते हैं कि लोग हमारी अदालतों के काम करने के तरीके से तंग आ चुके हैं, तो न्यायिक प्रणाली पर इससे अधिक गंभीर आरोप और क्या हो सकता है! उनका यह दावा कि न्यायपालिका को केवल न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों के लिए संचालित होने वाली संस्था नहीं होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण आलोचना है जो भारत के कानूनी ढांचे के भीतर प्रणालीगत मुद्दों को रेखांकित करती है।

यह दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत असंतोष का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि एक अवलोकन है जो समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और टिप्पणियों में प्रतिध्वनित हुआ है। पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय में सप्ताह भर चलने वाली विशेष लोक अदालत के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की टिप्पणी, अदालत की हालिया कार्रवाइयों और टिप्पणियों के संदर्भ में विशेष रूप से मार्मिक है। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित करने की कड़ी आलोचना की, जो एक कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं, जिसने काफी ध्यान आकर्षित किया था। उनके मामले ने मीडिया में महत्वपूर्ण कवरेज प्राप्त करने के साथ–साथ व्यापक प्रणालीगत मुद्दों का एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया पर एक व्यापक टिप्पणी भी है।

सिसोदिया, बेशक, एक हाई–प्रोफाइल व्यक्ति हैं, लेकिन भारतीय जेलों में बंद लाखों गुमनाम विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा पर विचार करें, जो या तो उचित सुनवाई के बिना या जमानत हासिल करने के साधनों के बिना जेल में हैं। उनमें से अधिकांश, अक्सर वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, तथा खुद को कानूनी अधर में फंसा हुआ पाते हैं। उनके मामले अनिश्चित काल के लिए विलंबित हो जाते हैं। यह स्थिति इस बात की स्पष्ट याद दिलाती है कि न्यायिक प्रणाली की विफलताएं उन लोगों को कैसे प्रभावित करती हैं जिनके पास तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप को आकर्षित करने के लिए संसाधन या बुद्धि की कमी होती है। विचाराधीन कैदियों का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों और निर्णयों के कारण इस पर फिर से ध्यान गया है। कई मामलों में, विचाराधीन कैदी अपने मुकदमों की सुनवाई शुरू हुए बिना ही लंबे समय तक जेल में रहते हैं, जो न्याय वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण दोष को उजागर करता है। न्यायिक प्रक्रिया में देरी, न्यायिक कर्मियों की कमी और प्रणालीगत अक्षमताओं के कारण यह समस्या और भी बढ़ जाती है, जो मामलों के समय पर निर्णय को रोकती हैं। इस संदर्भ में, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की टिप्पणी सुधार की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को दर्शाती है। न्यायिक प्रणाली, जैसा कि यह है, अपनी प्रक्रियात्मक देरी और अक्षमताओं के बोझ तले संघर्ष करती हुई प्रतीत होती है। आलोचना केवल व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में नहीं है, बल्कि समय पर न्याय देने में प्रणालीगत विफलता के बारे में है। व्यापक निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। वह प्रणालीगत बदलाव की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं, जिसमें न केवल प्रक्रियागत देरी बल्कि अंतर्निहित अक्षमताएं भी शामिल हैं जो प्रणाली को प्रभावित करती हैं। न्यायपालिका की भूमिका केवल निर्णय देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि न्याय निष्पक्ष और शीघ्रता से दिया जाये। जब प्रणालीगत मुद्दे इस भूमिका को कमजोर करते हैं, तो यह न्यायिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास और भरोसे को खत्म कर देता है। न्यायपालिका को एक ऐसी संस्था बनने का प्रयास करना चाहिए जो सभी के लिए न्याय के सिद्धांतों को कायम रखे, न कि केवल एक निकाय जो अपने स्वयं के प्रक्रियात्मक ढांचे के दायरे में काम करता है। ध्यान इस ओर केंद्रित होना चाहिए कि प्रणाली को सभी व्यक्तियों की जरूरतों के लिए अधिक सुलभ, कुशल और उत्तरदायी बनाया जाये, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

निस्संदेह, न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियां जटिल और बहुआयामी हैं। उन्हें तत्काल चिंताओं, जैसे कि विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा, और दीर्घकालिक संरचनात्मक मुद्दों, दोनों को संबोधित करने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, न्यायाधीशों और न्यायालय कर्मियों की संख्या बढ़ाने और प्रक्रियात्मक दक्षता बढ़ाने के प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके अतिरिक्त, देरी और अक्षमताओं के मूल कारणों, जैसे पुरानी प्रक्रियाएं और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, को संबोधित करना अधिक प्रभावी न्यायिक प्रणाली बनाने में आवश्यक होगा।

हाल के आंकड़े स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हैं। 2023 तक, भारत की जेलों की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा विचाराधीन कैदियों का है। यह चौंका देने वाला आंकड़ा एक गंभीर मुद्दे को उजागर करता हैरू भारतीय जेलों में बंद व्यक्तियों का एक बड़ा हिस्सा अभी तक मुकदमे का सामना नहीं कर पाया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2.5 लाख से अधिक लोग विचाराधीन कैदी थे। इनमें से कई व्यक्ति लंबे समय तक जेल में रहे हैं, अक्सर दोषी पाये जाने पर उन्हें मिलने वाली सजा की अवधि से अधिक। इन विचाराधीन कैदियों की जनसांख्यिकी एक परेशान करने वाला पैटर्न दिखाती है। उनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या समाज के वंचित वर्गों से आती है। अध्ययनों से पता चला है कि गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक–आर्थिक नुकसान लंबे समय तक हिरासत में रहने से निकटता से जुड़े हुए हैं। कई विचाराधीन कैदी हाशिए के समुदायों से हैं,अनुसूचित जाति और जनजाति, तथा आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले लोग। इन व्यक्तियों के पास अक्सर कानूनी प्रतिनिधित्व या जमानत प्राप्त करने के लिए संसाधन नहीं होते हैं, जिसके कारण उन्हें बिना किसी सुनवाई के लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ता है। विचाराधीन कैदियों की समस्या जमानत प्राप्त करने की प्रणालीगत समस्या से और भी जटिल हो जाती है। हजारों लोग इसलिए जेल में नहीं रहते क्योंकि उन्हें दोषी ठहराया गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जमानत के लिए आवश्यक जमानत राशि का प्रबंध नहीं कर सकते। जमानत देने में असमर्थता अक्सर वित्तीय बाधाओं के कारण होती है, जिससे कई लोगों के लिए अपनी रिहाई सुनिश्चित करना लगभग असंभव हो जाता है। यह वित्तीय बाधा भीड़भाड़ वाली जेलों की समस्या को और बढ़ा देती है और ऐसे व्यक्तियों की लंबे समय तक हिरासत में रहने में योगदान देती है जो अंततरू निर्दोष पाये जा सकते हैं। विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा न्यायिक प्रणाली की विफलताओं की एक कठोर याद दिलाती है। प्रणाली की अक्षमता न केवल व्यक्तियों को निष्पक्ष और समय पर सुनवाई के उनके अधिकार से वंचित करती है, बल्कि वंचितता के एक चक्र को भी बनाये रखती है जो असमान रूप से गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को प्रभावित करती है। वित्तीय बाधाओं के कारण जमानत प्राप्त करने में असमर्थता न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा को रेखांकित करती है और व्यापक सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है।इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जमानत प्रणाली में सुधार करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि यह उन लोगों को अनुचित रूप से दंडित न करे जो इसके खर्च वहन नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त, देरी को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि न्याय तुरंत दिया जाये। कानूनी सहायता सेवाओं में निवेश और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सहायता भी विचाराधीन कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ प्रणालीगत बाधाओं को कम करने में मदद कर सकती है।

जलवायु अनुकूल फसलें

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के चलते पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से हमारी खाद्य शृंखला को खतरा पैदा हो गया है। मानसून के पैटर्न में बदलाव, घातक गर्मी की लहरों, समुद्री जलस्तर में वृद्धि तथा आये दिन आने वाले समुद्री तूफान कृषि उत्पादन के लिये संकट पैदा कर रहे हैं। इस बाबत इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की हालिया रिपोर्ट में खतरों के प्रति चेताया गया है। निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभावों ने हमारे खेत–खलिहानों में दस्तक दे दी है, जिसका मुकाबला नई रणनीति बनाकर किया जा सकता है। आशंका जतायी जा रही है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से कृषि के क्षेत्र व फसलों की पैदावार में भारी कमी आ सकती है। खासकर छोटे किसानों के लिये यह संकट बड़ा है जो पूरी तरह से मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इन विषम परिस्थितियों में पैदावार को अक्षुण्ण रखने के लिये विशेष उपक्रम किये जाएं। इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक दशक पहले जलवायु अनुकूल खेती में नवाचारों को लेकर अपनी परियोजना शुरू की थी। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कई अधिक उपज वाली जलवायु अनुकूल फसलों की किस्मों का शुभारंभ करना इसी कड़ी का हिस्सा है। इस बाबत सरकार का कहना है कि अधिक पैदावार वाली गेहूं के बीजों की किस्मों को सफलता पूर्वक तैयार करने के बाद जलवायु प्रतिरोधी बीजों के साथ धान का रकबा बढ़ाना उसकी प्राथमिकता है। निस्संदेह, इस विकट पर्यावरणीय चुनौती का मुकाबला हम निरंतर स्वदेशी समाधानों के जरिये ही कर सकते हैं। जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की जा रही है। निस्संदेह, देश में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों की कोई कमी नहीं है,लेकिन जरूरत इस बात की है कि उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए। निस्संदेह, जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभावों से कृषि उत्पादन को संरक्षण देने और किसानों के हितों की रक्षा के लिये संसाधनों का बेहतर उपयोग बेहद जरूरी है। इसके साथ ही जल स्रोतों का संरक्षण, वन क्षेत्र की रक्षा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं के जरिये भूमि की उर्वरता बढ़ाने का उपक्रम भी करने की दरकार है। हमें खेती में कृत्रिम खादों के उपयोग में भी संयम बरतना चाहिये। इसी कड़ी में फसलों के विविधीकरण कार्यक्रम को भी गति देने की आवश्यकता है। इसके लिये किसानों को जागरूक और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। यह सुखद है कि देश के कई राज्यों में व्यापक पैमाने पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम को राष्ट्रव्यापी बनाया जाना चाहिये। इस दिशा में प्रोत्साहन योजनाएं किसानों का जैविक खेती अपनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। एक तथ्य यह भी कि इस दिशा में नई प्रौद्योगिकी तैयार कर लेने मात्र से ही समस्या का समाधान संभव नहीं है। जरूरत इस बात की है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों को खेतों तक पहुंचाया जाए। किसान सहजता से उनका उपयोग करते हुए फसलों के संरक्षण को गति दे सकें। दरअसल, किसान को व्यावहारिक रूप से संतुष्ट करना जरूरी भी है कि उसके लिये वास्तव में क्या उपयोगी है। देश में किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिये देशव्यापी सहमति बनाने की जरूरत है। इसके लिये आधुनिक अनुसंधान के साथ ही अनुभवजन्य अध्ययन को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सही मायनों में इन प्रयासों को गति देने के लिये अनुसंधान हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने तथा खेती के लिये उपयोगी निष्कर्षों को किसानों तक पहुंचाने की भी जरूरत है। लगातार भयावह होते परिदृश्य में इस चुनौती को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल करने की आवश्यकता है। इस हकीकत को जानते हुए कि हम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। एक बड़ी आबादी की सामाजिक सुरक्षा के लिये तमाम खाद्यान्न योजनाएं सरकारी अन्न भंडारों के जरिये चलायी जा रही हैं। जिसकी पूर्ति खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर ही की जा सकती है। यह तभी संभव है जब हमारी कृषि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का मुकाबला करने में सक्षम हो।

पेरिस ओलम्पिक का खट्टा-मीठा समापन

फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई को प्रारम्भ हुए 33वें ओलिम्पिक खेलों का समापन रविवार को हुआ। 126 पदकों के साथ अमेरिका (40 स्वर्ण) प्रथम, चीन दूसरे तथा जापान तीसरे क्रमांक पर रहा। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत ने पिछले टोक्यो ओलिम्पिक में कुल 6 मेडल पाये थे, लेकिन उसमें एक गोल्ड था। इस बार भी उसे कुल जमा 6 ही मिले– एक रजत और 5 कांस्य। उसका क्रमांक 71 रहा। छोटे–बड़े 62 देश ऐसे हैं जिन्हें कम से कम एक स्वर्ण पदक अवश्य मिला है। मनु भाकर एकमेव ऐसी खिलाड़ी रहीं जिन्होंने दो पदक पाये। एकमात्र रजत नीरज चोपड़ा को मिला जिन्होंने पिछली प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता था। नीरज इस बार अपने परम्परागत प्रतिस्पर्धी अरशद नदीम (पाकिस्तान) से आगे भाला फेंक नहीं पाये। भारत के प्रदर्शन ने फिर साबित कर दिया कि खेल शक्ति बनने के लिये देश का आकार या जनसंख्या जिम्मेदार नहीं बल्कि सरकारों का रवैया, समाज का नजरिया, खिलाड़ियों को मिलने वाला समर्थन व सम्मान, संसाधनों व सुविधाओं की उपलब्धता जैसे तथ्य मुख्य कारक होते हैं। पदक तालिका में शीर्ष पर खड़े अमेरिका की जनसंख्या भारत के मध्य वर्ग के बराबर भी नहीं है, तो वहीं दूसरे क्रमांक पर भारत से आकार में काफी छोटा जापान है। चीन तीसरे स्थान पर है जो भारत की ही तरह बड़ी आबादी तथा विशाल भूभाग वाला देश है। जज्बा– बस यही मायने रखता है। फिर चाहे वह देश का हो या खिलाड़ियों का। भारत में खिलाड़ियों के पास जज्बा और काबिलियत तो है, लेकिन सरकारें निराश करती है। खेलों को गम्भीरता से लेने वाले राज्यों की संख्या गिनाने के लिये एक हाथ की उंगलियां भी काफी हैं। शेष औपचारिकता निभाते हैं और इस क्षेत्र को भी अपनी सियासत का अखाड़ा मानते हैं। सत्ता से जुड़े लोग खेल संगठनों पर काबिज हैं। जिस संगठन की सरकार से जितनी निकटता होगी वह सरकार से उतना ही अनुदान खींच लाता है शासन से सहूलियतें जुटाई जाती हैं, अध्ययन के नाम पर विदेशी दौरे होते हैं, प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के अनुपात में बड़ा सा अधिकारियों का दल होता है। टूर्नामेंट के प्रदर्शनों का विश्लेषण नहीं होता, न ही खर्चों की समीक्षा होती है। ओलिम्पिक हों या कोई और स्पर्धा, लौटने पर खराब प्रदर्शन के लिये थोड़ी–बहुत शिकायतें होती हैं या आलोचना होती है, वह भी खिलाड़ियों की। सरकारें, खेल संगठन एवं अधिकारीगण बच निकलते हैं। ऐसे राज्य जो ढंग के दो खिलाड़ी भी पैदा नहीं करते, वे खेल मंत्रालय से करोड़ों रूपये उठा लाते हैं। जिन कथित पिछड़े राज्यों में खिलाड़ियों को विकसित करने की असीम सम्भावना होती है वहां के खिलाड़ी और संगठन पाई–पाई को तरसते हैं।

खैर, ये वे ही पुरानी बातें हैं जो पिछले हर ओलिम्पिक के बाद भारत में कही और दोहराई जाती हैं। इस बार के ओलिम्पिक ने तो यह बताया है कि लोगों में सरकार अगर भेद–भाव और नफरत के बीज बो दे तो उसकी कंटीली शाखाएं हर जगह पर उग आती हैं। इसके कारण खेल का क्षेत्र कैसा विषाक्त बन जाता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पेरिस ओलिम्पिक भारत को दिखा गया। देश का प्रतिनिधित्व करने वाली विनेश फोगाट ने एक ही दिन में कुश्ती के तीन मुकाबले जीत लिये थे और स्वर्ण पदक पहुंच में था। अंतिम मुकाबले के पहले उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। बाहर हो गईं। ये वही विनेश हैं जिन्होंने कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस आरोप के साथ मोर्चा खोला था कि ब्रजभूषण द्वारा उनके समेत कई महिला पहलवानों का उत्पीड़न किया गया है। इसे लेकर देश भर के पहलवानों एवं महिला सम्मान के पक्ष में खड़े लोगों ने दिल्ली और कई जगहों पर प्रदर्शन किये थे। दिल्ली में इनके साथ पुलिस ज्यादतियां भी हुईं। विनेश के साथ साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया आदि विशेष प्रताड़ित किये गये। ब्रजभूषण को उनके गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से इसी प्रकरण के चलते इस बार टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन उनके पुत्र करण भूषण सिंह जीत आये। अपने खिलाफ चले आंदोलन की रत्ती भर परवाह न करते हुए ब्रजभूषण पहले भी कह चुके थे–दबदबा है और दबदबा रहेगा।श 55 किलो केटेगरी में खेलने वाली विनेश को क्यों 50 किलोग्राम श्रेणी में उतारा गया और कैसे दल के पास खान–पान विशेषज्ञों के रहते उनका वजन बढ़ा, इसका जवाब भी उसी दबदबे में छिपा हुआ हो सकता है। उसकी ओर विनेश ने पहले ही अंदेशा जताया था कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। घोर निराशा में विनेश ने संन्यास की यह कहकर घोषणा कर दी– श्मैं हार गई, कुश्ती जीत गयी। पेरिस ओलिम्पिक के दौरान हुए इस घटनाक्रम ने भारत से उसकी एक शानदार पहलवान को छीन लिया। ब्रजभूषण के समर्थक और नफरतियों की बांछें खिल गईं तथा वे अपनी ही खिलाड़ी के खिलाफ हो गये। घृणा जो न कराये सो थोड़ा! वैसे नफरत व वर्चस्व भाव से हुई इस घटिया हरकत के बीच प्रेम व खेल भावना की ठंडी बयार भी पेरिस से चलकर भारत और पाकिस्तान तक पहुंची है। नीरज की मां सरोज देवी ने अपने बेटे के रजत को ही गोल्ड बताया और कहा कि श्गोल्ड जिसका है वह भी हमारा बेटा है। ऐसे ही सरहद पार बैठी अरशद की मां रजिया परवीन ने नीरज की जीत के लिये यह कहकर दुआएं की थीं वह अरशद का भाई व मित्र होने के नाते उनका बेटा है। देश हाल के वर्षों में काफी कुछ गंवा चुका है लेकिन दो कथित दुश्मन देशों के खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा में कटुता की बजाये उठी गर्मजोशी जब दो मांओं के दिलों से आशीषें बरसाने वाली घटना बनी, तो लगा कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। भारत के लिये पेरिस ओलिम्पिक का यही प्रतिफल है– कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है।

वक्फ विधेयकः सुधार की खाल में सांप्रदायिकता

आखिरकार, 1995 के वक्फ कानून में संशोधनों के विधेयक को, फिलहाल एक संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक के लिए ऐसे सलूक को, निश्चित रूप से अपवाद ही कहा जाएगा। संसद के पिछले सत्र तक बिना किसी समुचित चर्चा के बल्कि बिना चर्चा के ही, विधेयकों पर संसद से मोहर लगवाने के अपने उतावलेपन के लिए कुख्यात मोदी सरकार का, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही वक्फ विधेयक पर शविस्तृत और बहुपक्षीयश चर्चा की जरूरत स्वीकार कर लेना और विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के लिए राजी होना, बेशक हाल के आम चुनाव से निकल कर आई सच्चाइयों को प्रतिबिंबित करता है। इससे तो कोई इंकार ही नहीं कर सकता है कि अब संसद में राजनीतिक ताकतों का संतुलन काफी बदला हुआ है। इस बदले हुए संतुलन का ही संकेतक है कि एक ओर सत्ताधारी भाजपा और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्ष की ताकत, लगभग बराबर है और इन हालात में मुख्यतरू तेलूगू देशमङ्ख तथा जनता दल–यूनाइटेड के साथ गठबंधन के बल पर ही, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच पाए हैं। जाहिर है कि सत्ता में होते हुए भी भाजपा इन हालात में, खासतौर पर मोदी के राज के पिछले कार्यकाल की तरह, बहुमत की मनमानी चलाने की उम्मीद नहीं कर सकती है। हालांकि, उसके पास सरकार चलाने के लिए जरूरी बहुमत है, फिर भी विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत के सामने, यह बहुमत भी मनमानी चलाने के लिए काफी नहीं है। फिर वक्फ विधेयक के खास मामले में, यह सिर्फ बहुमत के लिए जरूरी संख्या का मामला नहीं रह सकता था। तेलुगू देशम और जनता दल–यूनाइटेड ने बेशक, इस विधेयक पर भी कोई भाजपा से खुद को अलग नहीं कर लिया था। सहयोगी पार्टियों का सत्ता पक्ष के लिए ऐसा कोई धर्मसंकट पैदा करना तो दूर रहा, लोकसभा में जदयू के प्रवक्ता ने औपचारिक रूप से इस विधेयक की पैरवी भी की थी। इसके बावजूद, यह कहना सही नहीं होगा कि ये सहयोगी पार्टियां इस विधेयक का कोई बढ़–चढ़कर समर्थन कर रही थीं। उल्टे प्रस्तावित विधेयक की विपक्ष की प्रबल आलोचनाओं से ये पार्टियां साफ तौर पर असहज नजर आ रही थीं और विधेयक की उनके समर्थन के सारे तर्क, बचाव के तर्क थे। वर्ना उनकी दलीलों के पीछे छुपी बेचैनी आसानी से पढ़ी जा सकती थी। और ऐसा होना, इस संशोधन विधेयक के लाए जाने की पूरी कसरत के अर्थ और मंतव्यों के चलते होना स्वाभाविक ही था, जिनको विपक्ष द्वारा बलपूर्वक रेखांकित किया जा रहा था। पहला सवाल तो यही था कि वक्फ कानून में इस तरह के संशोधनों की आवश्यकता ही क्या थी? संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश करते हुए, संसदीय कार्यमंत्री तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू तथा सत्ता पक्ष के अन्य वक्ताओं द्वारा भी इसके तमाम दावे किए जाने के बावजूद कि परामर्श की एक विस्तृत प्रक्रिया से गुजर कर उक्त संशोधन प्रस्ताव तैयार किए गए थे, यह सच किसी से छुपा हुआ नहीं था कि उक्त विधेयक किसी भी तरह की पॉपूलर डिमांड पर नहीं लाया गया था। उल्टे मुस्लिम समुदाय, जिसके धार्मिक आचार के हिस्से के तौर पर दान–पुण्य के कार्य के तौर पर, चल–अचल संपत्तियां वक्फ करने की रिवायत आती है और इन संपत्तियों की समुचित व्यवस्था के लिए ही वक्फ कानून बनाया गया है, और मुस्लिम धार्मिक राय के बड़े हिस्से द्वारा इस पूरी कसरत को गहरे संदेह की नजर से ही देखा जा रहा था। ऐसा भी नहीं है कि वक्फ कानून में संशोधन की इस कसरत की आलोचना करने वाले इसका दावा कर रहे हों कि 1995 का वक्फ कानून अपने आप में कोई आदर्श कानून था और उसमें किसी संशोधन या सुधार की कोई गुंजाइश या आवश्यकता ही नहीं थी। यह तो खैर किसी का भी कहना नहीं था कि वक्फ संबंधी सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी, जिसमें कोई कमजोरियां या खामियां थी ही नहीं। लेकिन, सबसे पहली बात तो यह कि इस पूरी कसरत के पीछे सत्ताधारी भाजपा की नीयत ही संदेह के घेरे में थी। बेशक, सत्ता पक्ष की ओर से गरीब–मुसलमानों की भलाई की चिंता का जमकर दिखावा किया जा रहा था। वर्तमान व्यवस्था में मुस्लिम महिलाओं के निर्णय प्रक्रियाओं से बाहर ही छूटे रहने पर काफी आंसू बहाए जा रहे थे। वक्फ बोर्डों तथा वक्फ से जुड़ी अन्य संस्थाओं के बेशुमार मामलों–मुकदमों में फंसे होने पर बड़ा अफसोस जताया जा रहा था। और वक्फ की संपत्तियों, विशेष रूप से जमीनों का, मुसलमानों की भलाई के लिए ठीक से उपयोग न हो पाने का, खूब रोना रोया जा रहा था। लेकिन, एक ओर जिस तरह के पैट्रनाइजिंग सुर में और दूसरी ओर, मुस्लिम समुदाय की संस्थाओं व समुदाय के नेताओं के प्रति हिकारत के सुर में, ये सारी दलीलें दी जा रही थीं, उनसे कोई समझ सकता था कि इस कसरत के पीछे कम से कम मुसलमानों का भला करने की इच्छा नहीं थी। उल्टे जिस तरह से प्रस्तावित संशोधनों के जरिए, सुधार के नाम पर वास्तव में वक्फ की संपत्तियों पर केंद्र सरकार के नियमनकारी नियंत्रण को उल्लेखनीय तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जा रही था, वह किसी से भी छुपा नहीं रहा। वक्फ की संपत्तियों के रिकार्डों को चुस्त–दुरुस्त बनाने के नाम पर, न सिर्फ वक्फ संपत्तियों के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्रैशन व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है बल्कि इन संपत्तियों के संबंध में तमाम जानकारियां नया कानून बनने के छरू महीने के अंदर–अंदर अपलोड किए जाने तथा तमाम नयी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन उक्त पोर्टल के जरिए ही वक्फ बोर्डों के सामने पेश किए जाने के तकनीकी रूप से उन्नत किए जाने के नजर आने वाले किंतु वास्तव में सब कुछ ज्यादा केंद्रीयकृत करने वाले प्रावधान किए गए हैं। लेकिन, इससे भी ज्यादा समस्यापूर्ण तरीके से पुराने कानून की उस धारा–40 को हटा दिया गया है, जिसके तहत वक्फ ट्रिब्यूनलों को यह तय करने का अधिकार होता था कि क्या कोई संपत्ति वक्फ होने लायक है। ट्रिब्यूनलों की जगह पर, अब जिला कलेक्टर को ऐसे मामलों में अंतिम निर्णयकर्ता बना दिया गया है। और जब तक कलेक्टर द्वारा संबंधित संपत्ति के वक्फ लायक होने की अंतिम रिपोर्ट सरकार को नहीं दे दी जाती है, संबंधित संपत्ति को वक्फ संपत्ति की तरह नहीं बरता जा सकेगा। इसका अर्थ यह है कि जब तक कि सरकार मामले का फैसला नहीं कर देती है, वक्फ बोर्ड ऐसी किसी संपत्ति का नियंत्रण नहीं ले सकता है। इसके साथ ही, संशोधन प्रस्तावों के जरिए केंद्र सरकार को शकिसी भी वक्फ का, कभी भी ऑडिट किए जाने का निर्देश देनेश का अधिकार दे दिया गया है। वक्फ बोर्डों पर लगाई गई इसकी शर्त के ऊपर से है कि राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए ऑडिटरों के पैनल में से किसी ऑडिटर से हर साल अपने खातों का ऑडिट कराएंगे। उपयुक्त खाते नहीं रखने पर मुतवल्लियों पर जुर्माने भी लगाए जा सकेंगे।

केंद्रीयकरण के ऐसे ही एक और कदम में, वक्फ ट्रिब्यूनलों को अब तीन सदस्यीय निकाय के बजाय, सिफ दो सदस्यीय निकाय बना दिया जाएगा। इसके ऊपर से अब ट्रिब्यूनल में एक जिला जज होगा और दूसरा सदस्य, राज्य सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक का अधिकारी होगा। इसके बावजूद, अब वक्फ ट्रिब्यूनलों के निर्णयों की अंतिमता खत्म हो जाएगी और कोई भी पीड़ित पक्ष, इन निर्णयों के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। विवादित संपत्तियों के कलेक्टर के अंतिम रिपोर्ट न देने तक वक्फ न माने जाने के साथ जुड़कर, ट्रिब्यूनल के निर्णय की अंतिमता खत्म करने की व्यवस्था, वक्फ की व्यवस्था को ही अस्थिर करने का काम करेगी। इससे भी ज्यादा समस्यापूर्ण यह है कि अब वक्फ की परिभाषा को ही बदल दिया गया है। अब संपत्ति का कोई कानूनी मालिक ही, औपचारिक डीड के जरिए संपत्ति वक्फ कर सकेगा, वह भी तब जबकि वह शकम से कम पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो।श महत्वपूर्ण है कि इन संशोधनों के जरिए शउपयोग के जरिए वक्फश के विचार को खत्म ही कर दिया गया, जो इसकी इजाजत देता था कि इस रूप में उपयोग होता आ रहा होने के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ मान लिया जाए, भले ही उसकी मूल डीड विवादित हो। परंपरागत रूप से अक्सर वक्फ की जाने वाली संपत्तियां मौखिक रूप से ही इसके लिए समर्पित की जाती थीं और औपचारिक दस्तावेजीकरण काफी बाद में ही आया है। दूसरी ओर, वक्फ संपत्ति और सरकारी संपत्ति के दावों में किसी टकराव की सूरत में संपत्ति पर सरकार का दावा ही माना जाएगाकृशकोई सरकारी संपत्ति, इस कानून के बनने से पहले या बाद में, अगर एक वक्त संपत्ति के रूप में शिनाख्त की जाती है या वक्फ संपत्ति घोषित की जाती है, तो उसे वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा।श जाहिर है कि यह सब वक्फ की पूरी की पूरी व्यवस्था को अस्थिर करने का ही काम कर सकता है। प्रसिद्ध विधिवेत्ता तथा कानून के शिक्षक, फैजान मुस्तफा अकारण ही नहीं कहते हैं कि, सैकड़ों साल पहले वक्फ की संपत्तियों में विहित किए गए अधिकारों को एक निष्पक्ष न्यायिक निर्धारण के बिना कार्यपालिका के अधिकारी हाथ में नहीं ले सकते हैं। हैरानी की बात नहीं है कि इसकी व्यापक रूप से आशंकाएं पैदा हो गई हैं कि इन संशोधनों के जरिए सरकार, वक्फ की संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। यह मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं की और इस लिहाज से मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता को ही छीनने की कोशिश है। और अपने हिंदुत्ववादी बुनियादी समर्थन आधार को ठीक यही संदेश देना, इस विधेयक को लाने के पीछे मोदी सरकार का मकसद है। इस मकसद का इससे स्पष्टङ्ख संकेत और क्या होगा कि नये कानून के तहत, अपनी संपत्ति वक्फ करने के लिए तो संबंधित व्यक्ति के शपांच साल से इस्लाम का पालन कर रहा होनेश की शर्त लगाई गई है, जबकि केंद्रीय वक्फ काउंसिल, राज्य वक्फ बोर्ड तथा वक्फ ट्रिब्यूनलों जैसी वक्फ व्यवस्था की महत्वपूर्ण संस्थाओं में गैर–मुसलमानों को लाने के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। हैरानी की बात नहीं है कि विपक्ष ही नहीं, जदयू तथा तेदेपा जैसी भाजपा की सहयोगी पार्टियां भी इस पर असुविधा महसूस कर रही हैं, हालांकि उनसे ऐसे किसी सैद्धांतिक मुद्दे पर सरकार की गाड़ी पलटने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। फिर भी, इस वजह से भी मोदी सरकार ने वक्फ विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के लिए भेजना मंजूर किया है। यह दूसरी बात है कि लोकसभा में विधेयक लाने के जरिए, उसने अपने मूल समर्थन आधार को यह संदेश तो दे ही दिया है कि मुसलमानों को कोने में धकियाने की मुहिम मोदी–3 में भी जारी है और जारी रहेगी।

25000 रू0 नगद, चोरी करने के उपकरण तथा एक अर्टिगा कार पुलिस ने किया बरामद

अवध की आवाज ब्यूरो

मथुरा। थाना बलदेव पुलिस, सर्विलांस व स्वाट टीम की चोरी की योजना बनाते हुए यमुना एक्सप्रेस–वे ग्राम दौलतपुर अंडरपास के पास बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़, दौराने पुलिस मुठभेड़ 02 अभियुक्तगण हुए घायल सहित 06 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से अवैध शस्त्र मय कारतूस, पीली व सफेद धातु के आभूषण, 25000 रू0 नगद, चोरी करने के उपकरण तथा एक अर्टिगा कार बरामद। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा के आदेशानुसार अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महावन के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बलदेव, सर्विलांस व स्वाट टीम की दिनांक 13/14.08.2024 की रात्रि में चोरी की योजना बनाते हुए यमुना एक्सप्रेस–वे ग्राम दौलतपुर अंडरपास के पास बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़, दौराने पुलिस मुठभेड़ 02 अभियुक्तगण 1. रामेश्वर पुत्र राम भरोसे निवासी पारोली सिकरवार थाना फतेहाबाद जनपद आगरा 2. इंद्रपाल उर्फ छिगा पुत्र किताब सिंह निवासी झोरियन थाना पिनाहट जनपद आगरा हुए घायल सहित अन्य 04 अभियुक्तगण 1. हरिकांत निषाद पुत्र राम प्रकाश निवासी पारोली सिकरवार 2.महेंद्र सिंह पुत्र गयादिन निवासी ग्राम झोरियन थाना पिनाहट जनपद आगरा 3.रामचंद्र पुत्र रामविलास निवासी झोरियन थाना पिनाहट जनपद आगरा 4.विवेक उर्फ सुनील पुत्र किताब सिंह निवासी झोरियन थाना पिनाहट जनपद आगरा को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगणों के कब्जे से पीली धातु का चूड़ियां, सफेद धातु की एक जोडी पायल, 25000 रू0 नगद, चोरी करने के उपकरण, दो अदद अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 अदद खोखा व 04 अदद जिन्दा कारतूस तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त करने हेतु एक अर्टिगा कार बरामद की गयी । घायल अभियुक्तगणों को उपचार हेतु अस्पताल में भेजा गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बॉलीवुड स्टार थीम वॉक 2के 24 सीजन 3 रनवे और अवार्ड शो का आयोजन हुआ

लखनऊ। एंजल्स कास्टिंग हब और वाईआईएमए इवेंट्स द्वारा आयोजित बॉलीवुड स्टार थीम वॉक 2के24 सीजन 3 रनवे और अवार्ड शो का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस आयोजन में बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने शिरकत की और इसे बेहद सफल बनाया। इस भव्य आयोजन के आयोजक थे, सबसे कम उम्र के कास्टिंग निर्देशक मिस्टर अंश और अभिनेत्री एंजेल नीलिमा, जो जी म्यूजिक कंपनी की प्रसिद्धि हैं। उन्हें हाल ही में दिवा यूनिवर्स ऑफ इंडिया 2के23 और ग्लोबल फेस ऑफ यूपी 2के22 के खिताब से नवाजा गया है। इसके अलावा, उन्होंने इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2के24 और इंफ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2के24 भी प्राप्त किया है। नीलिमा एक सिविल इंजीनियर और पत्रकार भी हैं। उन्होंने लखनऊ में इस इवेंट के सीजन 1, 2 और अब 3 का आयोजन किया है, जो कि उनकी प्रतिबद्धता और सफलता का प्रतीक है। इस आयोजन में विशेष अतिथि के रूप में बॉलीवुड अभिनेत्री निहारिका रायजादा उपस्थित रहीं। निहारिका मिस इंडिया यूके 2010 का ताज पहन चुकी हैं और मिस इंडिया वर्ल्डवाइड 2010 की उपविजेता भी रही हैं। वह प्रसिद्ध बॉलीवुड संगीतकार ओपी नैय्यर की पोती हैं और उन्होंने आईबी71, मसान, 6—5=2, डैमाडोल, टोटल ध ामाल और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों में काम किया है। इस इवेंट में जूरी सदस्य के रूप में आलोक मिश्रा, हेमा मिश्रा और नेहा कश्यप ने भाग लिया। ध्रुव शर्मा, सोनम वरवानी, नैंसी मौर्य, सिमरन यादव, प्रियांशी पांडे, और खुशी सक्सेना को इंफ्लुएंसर अवार्ड से नवाजा गया। इस शो में सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर संजीव और अली तथा सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मिस कनिका सराफ और पूनम भारती शामिल रहीं, जिन्होंने अपने अद्वितीय कौशल से इस इवेंट को और भी खास बनाया। साजिया खान, आकांक्षा, अदिति सिंह, और आशुतोष त्रिपाठी को इस भव्य इवेंट के विजेता घोषित किया गया। इस इवेंट को आलोक मिश्रा, एब्बी चौध ारी, डिवाइन, करण, ब्रान कलेक्टिव और शिवम का समर्थन प्राप्त हुआ। इस आयोजन की सफलता के लिए टीम के सभी सदस्यों सेलिब्रिटी एंकर ऋषभ वर्मा (आरवी), अमित गुप्ता, उत्कर्ष, श्रेया चौधरी, और आशीष विवान का विशेष सहयोग रहा। इसके अलावा, सिंगर रागमन और दिव्यांशी, सभी फोटोग्राफरों, इंडिया फर्स्ट वन मिलीयनर शो की टीम, मीडिया पार्टनर्स, और सभी अतिथियों और प्रतिभागियों को भी धन्यवाद दिया गया।

आईटी कॉलेज लखनऊ में शुरू हुए बीटेक और ये प्रोफेशनल कोर्सेज'

लखनऊ। लखनऊ के आईटी कॉलेज में अब प्रोफेशनल कोर्स की भी शुरुआत हो गई है।इसाबेला थोबर्न कॉलेज सोसाइटी, जिसकी स्थापना 138 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया के पहले महिला कॉलेज के रूप में हुई थी, ने लगातार शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। 2017 में, इसके तत्वावधान में, इसाबेला थोबने कॉलेज (व्यावसायिक अध्ययन) (आईटीसीपीएस) की स्थापना की गई, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है। डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविध्यालय से संबद्ध और एआईसीटीई ध्द्वारा अनुमोदित आईटीसीपीएस ने अब बीबीए कार्यक्रम और चार ठज्मबी पाठ्ध्यक्रम शुरू किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, कप्यूटर विज्ञान, और जैव सूचना विज्ञान) डॉ ई एस चार्ल्स, इसाबेला थोबर्न कॉलेज की अध्यक्ष और आई टी सी पी एस के निदेशक और डॉ दीपिका डेल्सा डीन (कार्यवाहक प्रिंसिपल, आई टी सी पी एस) उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल न केवल लैंगिक असमानता को संबोध ित करती है बल्कि महिलाओं की तकनीकी विशेषज्ञता को भी बढ़ाती है, जिससे वे तेजी से विकसित हो कर वैश्विक परिदृश्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो जाती हैं। आई टी सी पी एस पहला एकेटीयू संबद्ध कॉलेज है जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बीटेक की पेशकश करता है, जो पी सी एम और पी सी बी दोनों महिला छात्रों के लिए उपलब्ध है। इस मील के पत्थर का उध्देश्य महिलाओं को पेशेवर स्थिरता, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी और बेहतर आर्थिक और सामाजिक स्थिति प्रदान करना है, जिससे उन्हें विज्ञान और प्रौध्योगिकी में उत्कृष्टता हासिल करने का अधिकार मिलता है।

यमुनाः न हों परेशान, अभी दूर है खतरे का निशान

मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी हलचल

अवध की आवाज ब्यूरो

मथुरा। यमुना का जलस्तर बढ़ने से खादर के वाशिंदों में हल चल है। हालांकि अभी भी खतरे का निशान दूर है। मंगलवार की सुबह गोकुल बैराज से 17 हजार क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा था। ओखला बैराज से 30 हजार क्यूसेक पानी छोडा गया है। धीरे धीरे पानी का प्रवाह बढ रहा है लेकिन हाल फिलहाल यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को छू पाएगा इस बात की संभावना नहीं है। खतरे का निशान मथुरा में 165.3 सेंटीमीटर पर है। मंगलवार की सुबह जलस्तर खतरे के निशान से 92 सेंटीमीटर नीचे था, हालांकि जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। एई सिंचाई विभाग राकेश कुमार ने बताया कि यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को छू पाएगा इस बात की संभावना नहीं है। मथुरा में बाढ़ का खतरा नहीं होने के बावजूद यमुना में पानी पढ़ते ही लोगों के चेहरे फक्क पड जाते हैं। यमुना खादर में वृंदावन से गोकुल बैराज तक 250 से अधिक कॉलोनियों को अनाधिकृत रूप से विकसित हो जाना इसकी वजह है। हालांकि यमुना किनारे कई गांव भी हैं, यमुना में पानी बढने से इन गांवों में भी पानी घुसने का अंदेशा रहता है और एहतियातन लोगों को सतर्क कर दिया जाता है। वहीं मथुरा वृंदावन में बिना बाढ़ के ही हर साल बाढ जैसे हालात बन जाते हैं और बडी संख्या में लोगों को घरों से पलायन करने को मजबूर होना पड़ता है।

ई-खतौनी का कार्य पूरा, अब मिलेगी ऑनलाइन जानकारी

लखनऊ। राजस्व परिषद की तरफ से उत्तर प्रदेश में ई—खतौनी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके चलते ग्रामीणों को खतौनी की प्रविष्टियों के लिए अब छह वर्षों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ खतौनी से संबंधित ऑनलाइन जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉ. रजनीश दुबे ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मंडलायुक्तों व जिलाधि ाकारियों के साथ बैठक कर राजस्व कार्यों की समीक्षा की थी। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व वादों के निस्तारण में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीमा स्तंभ अभियान और अभिलेखों के आध ुनिकीकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि चकबंदी में शामिल गांवों को छोड़कर प्रदेश में ई—खतौनी का कार्य पूरा कर लिया गया है। घरौनी के कार्यों की भी समीक्षा की गई।अधिकारियों ने बताया कि जिन गांवों में घरौनी का काम पूरा नहीं किया जा सका है, वहां पर सर्वे आफ इंडिया के सहयोग से मंडलायुक्तों की निगरानी में दोबारा ड्रोन सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। घरौनी का काम इसी वर्ष दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। बैठक में राजस्व को लेकर उत्कृष्ट कार्य वाले सात जिलाधिकारियों को आनलाइन प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें आगरा के जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी, मीरजापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी, सहारनपुर के जिलाधिकारी मनीष बंसल, रामपुर के जिलाधिकारी जोगेन्द्र सिंह, सुलतानपुर की जिलाधि ाकारी कृतिका ज्योत्सना व जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के नाम शामिल हैं।

चोरी का मुकदमा वापस न लेने पर दी धमकी, सहमी किशोरी ने जहर खाकर दी जान

बांदा। चोरी के मुकदमे को वापस लेने की धमकी से आहत किशोरी ने जहर खाकर जान दे दी। तिंदवारी थाना क्षेत्र के गजनी गांव निवासी काजल (16) ने सुबह घर में जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसके माता–पिता को जानकारी हुई तो वह उसे लेकर तिंदवारी पीएचसी पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दोपहर के समय दम तोड़ दिया। मौसेरे भाई दीपेंद्र सिंह ने बताया कि 27 जुलाई को काजल के घर में चोरी हुई थी। चोर घर से जेवर और पांच हजार रुपये ले गए थे। काजल ने गांव के दो लोगो को चोरी करते हुए देख लिया था। इसी आधार पर काजल की मां अनीता देवी ने तीन अगस्त को गांव के दो लोगों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि चोरी के दोनों आरोपी काजल को धमका रहे थे। रविवार को भी उन्होंने रास्ते में काजल को रोककर धमकी दी थी कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया तो वह उसे व उसके परिवार को जान से मार देंगे। इसी धमकी के डर से उसने जहर खाकर खुदकुशी की है। काजल के पिता किसान हैं। उनके पास 15 बीघा जमीन है। एक भाई व दो बहनों में छोटी थी। घटना के संबंध में तिंदवारी थाना इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि किशोरी ने जहर खाकर खुदकुशी की है। परिजन जो चोरी की बात कह रहे हैं, उसमें दोनों पक्षों का विवाद चलता है। विवाद के चलते दोनों पक्षों की तहरीर मिली थी। जिस पर लड़की की मां की तहरीर पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। खुदकुशी के कारणों की जांच की जा रही है।

सौर क्रांति की ओर अग्रसर है यूपी

प्रदेश में 3840 मेगावाट क्षमता के 09 सोलर पार्कों से 528 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू

बुंदेलखंड और अन्य क्षेत्रों में हो रही सोलर पार्कों की स्थापना बायोमास ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में यूपी देश में दूसरे स्थान पर

लखनऊ। सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में यूपी देश में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में है। प्रदेश में 3840 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के 09 सोलर पार्कों की स्थापना की जा रही, इसमें 528 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू है। सौर ऊर्जा की प्राकृतिक संभावना वाले सर्वश्रेष्ठ चार राज्यों राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चात उत्तर प्रदेश देश में पांचवें स्थान पर है, जहां पर सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बृहद स्तर पर कार्य किया जा रहा, बुंदेलखंड और अन्य क्षेत्रों में सोलर पार्कों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष रूप से सोलर पार्कों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त हुआ है।ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने बड़े कदम बढ़ाए हैं। सोलर पार्क के अतिरिक्त घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाना, सोलर नगरों की स्थापना, कृषि फार्म को सौर ऊर्जा से बिजली देना, पंप स्टोरेज एवं जैव ऊर्जा का उत्पादन शामिल हैं। बायोमास ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी यूपी देश में दूसरे स्थान पर है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में 25 लाख घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, इससे लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। प्रदेश में सौर ऊर्जा से 22 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। इसमें 6 हजार मेगावाट निजी व सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना करके की जायेगी तथा 14 हजार मेगावाट क्षमता की सौर उपयोगिता परियोजनाएं व सोलर पार्क स्थापित किये जायेंगे। राज्य में अभी तक 3871.17 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय क्षमता स्थापित की गई है। कैप्टिव उपयोग, तीसरे पक्ष की बिक्री, डिस्कॉम, यूपीपीसीएल को बिजली की खुली बिक्री के तहत 2594 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड परियोजना स्थापित की गई। घरों में 375 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप

सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत 16.17 मेगावाट ग्रिड ट्यूबवेल को सौर ऊर्जा से संचालित किया गया। किसानों के निजी ऑनग्रिड पम्प का सोलराइजेशन के साथ पृथक कृषि विद्युत फीडरों का सोलराइजेशन कराया जायेगा। प्रदेश के 61 जिलों के गांवों में 886 मेगावाट के पेयजल पंपिंग स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित किए गए। पिछले एक वर्ष में 528 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड यूटिलिटी स्केल चालू किया गया है। 6800 मेगावाट यूटिलिटी स्केल परियोजनाओं को स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट के विकास के लिए योजना लागू की है, इसके तहत 39,250 मेगावाट क्षमता को मंजूरी मिली है, अब तक 22 सोलर पार्कों में 11,591 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं देश में स्थापित की जा चुकी है। इसमें से गुजरात राज्य में 12,150 मेगावाट क्षमता के 07 सौर पार्कों से अब तक 1,000 मेगावाट की स्थापना हुई। राजस्थान में 9,568 मेगावाट क्षमता के 10 सौर पार्क परियोजनाओं से 3,241 मेगावाट की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश में 4,330 मेगावाट क्षमता के 08 सौर पार्क परियोजनाएं, आंध्र प्रदेश में 4200 मेगावाट क्षमता के 05 सौर पार्क परियोजनाएं, झारखंड में 1,089 मेगावाट क्षमता की तीन फ्लोटिंग सौर परियोजनाएं, हिमाचल प्रदेश में 53 मेगावाट क्षमता की सोलर पार्क परियोजनाएं, कर्नाटक में 2,000 मेगावाट क्षमता की 02 सौर परियोजनाएं स्वीकृत हैं। उत्तर प्रदेश की गौरवपूर्ण उपलब्धि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में संभव हुई है।नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कर्मठता से लगे हुए यूपीनेडा के सभी कार्मिकों को हार्दिक बध ाई एवं शुभकामनाएं दी है।

स्वयं सहायता समूह हो ए प्रदर्शनी का हुआ अवलोकन

अवध की आवाज ब्यूरो
श्री प्रकाश गुप्ता

सीतापुर। मा0 विधायक सिधौली मनीष रावत, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुये सराहना की। मा0 विधायक सिधौली मनीष रावत द्वारा प्रदर्शनी में उत्पादों का क्रय भी किया गया। मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने सभी उत्पादों को देखा एवं उनकी सराहना करते हुये कहा कि इन प्रोडेक्टों को लोकल बाजारों में विक्रय किया जाये। मा0 विधायक सिधौली मनीष रावत तथा जिलाधिकारी अभिषेक आनंद द्वारा सफाई कर्मियों द्वारा निकाली गयी तिरंगा यात्रा रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक शासन के निर्देशों के क्रम में सफाई कर्मियों द्वारा रैली निकाली जा रही है, जिसके क्रम में आज कलेक्ट्रेट परिसर में सफाई कर्मियों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तथा सभी विकास खण्डों में भी सफाई कर्मियों द्वारा तिरंगा यात्रा रैली निकाली जायेगी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर सभी सरकारी व अर्द्धसरकारी स्थानों पर सजावट की गयी है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मा0 मुख्यमंत्री जी का जो आहवान है, उसके क्रम में ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग सभी लोग झण्डों का वितरण कर रहे हैं ताकि सभी लोग अपने–अपने घरों पर तिरंगा लगाते हुये स्वतंत्रता दिवस अच्छे से मनायें। सभी चौराहों की सजावट की गयी है। उन्होंने कहा कि नगरवासियों से अपील की कि सभी लोग अपने–अपने घरों पर तिरंगा लगायें और स्वतंत्रता दिवस के पर्व को सफल बनायें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नीतीश कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी हरिश्चन्द्र प्रजापति सहित विकास भवन के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके उपरान्त कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल, अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णा नंद तिवारी, जिला विकास अधिकारी हरिश्चंद्र प्रजापति ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर शहीदों की याद में मौन रखकर उन्हें याद किया। वहां पर उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारी ने विभाजन विभीषिका स्मृति की डॉक्यूमेंट्री को देखा व लगी हुये प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

उपचुनावः राजभर और अपना दल खाली हाथ

बीजेपी को 7, निषाद पार्टी को 2, रालोद को एक सीट पर मौका

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दस सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए में सीटों के बंटवारे पर सस्पेंस खत्म होता नजर आ रहा है। राज्य में दस सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, अभी तक चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। एनडीए के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर गुत्थी सुलझ गई है।इसका संकेत निषाद पार्टी प्रमुख और योगी सरकार के मंत्री डॉ. संजय निषाद के बयान के आधार पर मिलने लगे हैं।आज बुधवार को उपचुनाव के संबंध में मीडिया से मुखातिब मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा, एनडीए मझवा और कटेहरी में निषाद पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा। एनडीए 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए की 2 सीटों पर सहयोगी दल के सदस्य लड़ते हैं ऐसा इतिहास रहा है।हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीट जीते। जल्द ही 10 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया जाएगा।हम एनडीए को जिताएंगे।उनके बयान से स्पष्ट है, कि जिन दस सीटों पर चुनाव होने वाला है उनमें से दो सीट निषाद पार्टी को मिलेगी। गठबंधन के दल आरएलडी पहले ही पश्चिमी यूपी की सीट मीरापुर में अपनी तैयारी कर रही है।यह सीट आरएलडी विध ायक के इस्तीफे के बाद ही खाली हुई है।इस वजह से यहां आरएलडी का उम्मीदवार होना तय माना जा रहा है। एनडीए गठबंधन से सुभासपा को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने के संकेत पहले ही मिल चुके हैं। ऐसे ही संकेत अपना दल एस को लेकर भी हैं, माना जा रहा है कि अपना दल को भी कोई सीट नहीं मिलेगी।बीते दिनों ही जब उपचुनाव के संबंध में सुभासपा प्रमुख और योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर टिप्पणी कर रहे थे तो उन्होंने कहा, उपचुनाव में उन्होंने किसी सीट पर अपना दावा नहीं किया है बल्कि वो एनडीए के साथ पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम सब एनडीए के सहयोगी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में डटे हैं।उधर इंडिया गठबंधन में अभी सीटों पर पेंच फंसा है। कांग्रेस उपचुनाव के लिए पांच सीटें मांग रही है जबकि दूसरी ओर सूत्रों की मानें तो समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है लेकिन पार्टी गठबंधन के तहत दो से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है।

डीएम—एसपी ने निकाली तिरंगा यात्रा,लोगों को किया प्रेरित, विभाजन विभीषका किया शुभारंभ

उरई/जालौन। जनपद में हर घर तिरंगा फहराने की दिशा में जनपदवासियों को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का शुभारंभ पुलिस लाइन से हुआ। जहां जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। दोपहर 3 बजे पुलिस लाइन से शुरू हुई यह तिरंगा यात्रा जिले के विभिन्न चौराहों जैसे जिला परिषद चौराहा, अंबेडकर चौराहा, शहीद भगत सिंह चौराहा से होते हुए टाउन हॉल पहुंची। यात्रा के दौरान पुलिस जवानों ने देशभक्ति के नारों के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी उद्घोष किए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विभाजन विभीषण की संध्या पर आयोजित प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान यात्रा में शामिल सभी पुलिस जवानों के हाथों में तिरंगा था। वे उत्साहपूर्वक भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इस विशाल तिरंगा यात्रा में पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, एनसीसी कैडिट्स, स्काउड गाइड्स, छात्र–छात्राएं, सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान नागरिकों ने भी पुष्प वर्षा कर यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाया। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने कहा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक विभिन्न क्षेत्रों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज की विशाल तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग जाने की देश को स्वतंत्रता कैसे मिली। हम चाहते हैं कि इस अभियान से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदानों को याद रखा जाए। उन्होंने सभी जनपदवासियों से अनुरोध किया कि वे अपने घरों में राष्ट्रीय ध वज फहराकर इस अभियान में भाग लें और स्वतंत्रता के महत्व को समझें। इस तरह की भावनात्मक और प्रेरणादायक पहल से जनपदवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति गर्व और देशभक्ति की भावना को बल मिला है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार जायसवाल, होमगार्ड कमांडेंट राजेश कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी राम अयोध्या प्रसाद आदि सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी स्वयंसेवी मौजूद रहे।

शराब पीने से मना करने पर मकान मालिक की पिटाई,

6 लोगों ने ईंट से किया हमला, प्लॉट पर साथियों के साथ बैठे थे

उरई/जालौन। जालौन में निर्माणाधीन मकान में शराब पी रहे युवकों को मना करना एक मकान मालिक और उसके दो पुत्रों को भारी पड़ गया। शराब पीने से मना करने पर युवकों ने मकान मालिक और उसके पुत्रों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना को आसपास के लोगों ने देखा तो मौके पर पहुंचे। जिन्होंने युवकों को पकड़ने का प्रयास किया। मगर युवक अपनी बाइक छोड़कर मौके से भाग गए। इस घटना की शिकायत पीड़ित ने कोतवाली मे की। जहां लहूलुहान हालत में देखते हुए पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही इस मामले की जांच शुरू कर दी। घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तुलसी नगर स्थित कैला देवी मंदिर के पास की है। यहां के रहने वाले अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय राम लखन अपने घर के पास में खाली पड़े बाड़े पर काम करवा रहे हैं। जहां बुधवार आर्यन राजपूत और सुनील प्रजापति व उसके साथ 4 लोग जिनका नाम पता अज्ञात है, वह शराब पी रहे थे। जब अशोक अपने दोनों पुत्र गोपाल और सचिन के साथ अपने निर्माणाधीन मकान पर पहुंचा तो शराब पीते हुए आर्यन और सुनील शेट्टी व अन्य लोगों को देखा, तो उसने मना किया। इसी दौरान शराब पीने वाले लोगों ने अचानक गुम्मा व पत्थर से हमला करते हुए मारपीट शुरू कर दी। जिसमें अशोक व उसका पुत्र गोपाल व सचिन घायल हो गए। इस घटना को देखते हुए मोहल्ले के लोग वहां पहुंचे। जिन्होंने शराब के नशे में मारपीट करने वाले लोगों को पकड़ने का प्रयास किया। मगर वह लोग अपनी एक मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। घायल हालत में अशोक अपने पुत्रों के साथ मोहल्ले के लोगों के साथ कोतवाली पहुंचा। जहां पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मासूम भाई-बहन पर धारदार हथियार से हमला, सीसीटीवी से पकड़ा गया आरोपी

ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर थाना क्षेत्र में मासूम भाई–बहन पर एक सिरफिरे ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और उन्हें लहूलुहान कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के जरिए से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरसअल थाना सूरजपुर क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर ईटा में एक व्यक्ति ने 2 बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और फिर भाग गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और तत्काल प्रभाव से दोनों बच्चों को एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।, जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई। आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया गया। इसके बाद आरोपी आरोपी जय सिंह निवासी ईटा 1 मूल पता ग्राम बिलरा, थाना राठ, जिला हमीरपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि बच्चों के पिता से किसी बात को लेकर उसका विवाद था। उसी का बदला लेने के लिए हमला किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही बच्चों को काफी गंभीर चोट आई है लेकिन वह खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

मथुरा में पुलिस संरक्षण में फल फूल रहा नशे का कारोबार.......

मथुरा। जनपद मथुरा में पुलिस संरक्षण में फल फूल रहा नशे का कारोबार,शहर से लेकर देहात तक फैला है नशे के करोबार का जाल मदकपदार्थ करोबारियों को पुलिस दे रही है संरक्षण। धर्म की नगरी मथुरा वृंदावन में नशे के कारोबारी बेखौफ होकर मादक पदार्थों का कारोबार बडे इत्मिनान से कर रहे हैं।स्मौक,चरस,गांजा,अफीम,और डौडा का करोबार फल–फूल रहा है। लेकिन इलाका पुलिस है कि ड्रग सिंडिकेट की कारगुजारी पर अंकुश लगाने की बजाए मोटी कमाई के प्रयास में इन्हें संरक्षण दे रही में नशे का सामान आसानी से उपलब्ध हो रहा है। नशे के आदि लोगों की माने तो इन दिनों स्मैक,गांजा,शराब,भांग,चरस अफीम और डौडा पउडर के कोड वर्ड बना रखे है। उनके प्रयोग से कारोबारी इन्हें माल उपलब्ध करा देते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ड्रग सिंडिकेट का यह कारोबार मोबाइल फोन पर भी शुरू हो गया है। अधिक रेट मिलने पर ग्राहक द्वारा बताई गई ब्रांड की शराब या अन्य कोई मादक पदार्थ उसके द्वारा बताए गए ठिकाने पर सप्लाई किया जा खुला संरक्षण दे रही हैं। जब भी कोई व्यक्ति नशे के कारोबारियों की शिकायत पुलिस से करता है तो उसका नाम कारोबारियों तक पहुँच जाता है। जिसके चलते लोगों ने पुलिस से शिकायत करना बंद कर दिया है। वहीं अवैध नशा के शौकीन नशे की लत पुरी करने के लिए चोरी,छिनैती,लूट,जैसी आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। इस अवैध कारोबार को रोकने के लिए जिले के कई कप्तानो द्वारा लाख दावे तो किये लेकिन नशे का कारोबार दिन व दिन बढ़ता गया और सभी दावे

खोखले नजर आये। मथुरा वृंदावन को धार्मिक स्थल घोषित होने के बाद वार्ड वार मादकपदार्थ मास मीट अंडा शराब के लिए पाबंदी लगा दी गई लेकिन अवैध कारोबार करने वालों के लिए यह बंदी चांदी साबित हो गई है जिसके चलते अवैध कारोबार धडल्ले से चल रहे है। है। मथुरा वृंदावन के अधिकांश हिस्सों में नशे के कारोबारियों ने अपनी जडे पूरी तरह से जमा ली है। नशे की गिरफ्त में युवा वर्ग दिन प्रतिदिन फसता जा रहा है। आलम यह है कि 12 से 13 वर्ष के बच्चे भी नशे की चपेट में आते चले जा रहें हैं। यहां के अधिकांश क्षेत्र रहा है। लेकिन इलाका पुलिस है कि महीनादारी के लिए नशे के अवैध कारोबारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के बजाय उन्हें खुला संरक्षण प्रदान कर रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस इन नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाई करने के बजाय इन्हें

केएमयू के कुलाधिपति किशन चौधरी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ दिलवाते हुए

केएमयू के कुलाधिपति किशन चौधरी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत केएमयू में हुई संगोष्ठी, कुलाधिपति ने दिलवाई शपथ
नशे से मुक्ति पाकर ही भारत बन सकता है विकसित देश : किशन चौधरी
मिशन के रूप में अपनाएं अभियानः डा. डीडी गुप्ता
छात्र नशे की लत में न फंसे : डा. शरद अग्रवाल

अवध की आवाज ब्यूरो

मथुरा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान स्वतंत्रता दिवस 2024 मना रहा है जिसकी थीम विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र रखी गई है, जिसको लेकर केएम विश्वविद्यालय में संगोष्ठी कार्यक्रम

हुआ। इसमें विवि के कुलाधिपति एवं जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी ने कहा नशे से मुक्ति पाकर ही भारत विकसित देश हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भारत के सभी जनपदों में हो रहा है। नशे से मुक्ति प्राप्त कर हम लोग विकसित भारत बनाने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकते हैं। विवि के वाइस चांसलर डा. डीडी गुप्ता ने कहा कि यदि हम लोग इस कार्यक्रम को एक मिशन की तरह अपनाएं तो वह दिन दूर नहीं कि हमारा भारत देश नशे से मुक्त हो जाएगा। प्रो. वाइस चांसलर डा. शरद अग्रवाल ने कहा कि यह कार्यक्रम मुख्यतः केएम सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में इसलिए संचालित किया जा रहा है कि छात्र नशे की लत में न फंसे। डा. जेपी उपाध्याय ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई इसका उन्मूलन समाज की सहभागिता से ही हो सकता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी ने विश्वविद्यालय के सभी छात्र–छात्राओं एवं विवि के स्टाफ को नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हुए कहा कि हम सभी को नशीले पदार्थ के सेवन से दूर रहना चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस को हम सभी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बना रहे है। जिसमें आप सभी की सहभागिता होनी है। कार्यक्रम में परीक्षा नियंत्रक डॉ मनोज ओझा, विवि के साइंस एंड आट्‌र्स के डीन डा. धर्मराज, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के डीन डॉ सीपी वर्मा, एजुकेशन के डीन डॉ जेएस राठौर, प्रोफ़ेसर्स व अन्य कर्मचारियों में डॉ सुनील कुमार सिंह, डॉ विपिन सोलंकी, सुमित शर्मा, शैलेन्द्र शर्मा, चन्द्रेश कुमार, शेखर तिवारी, मुकेश कुमार, जगवीर सिंह, करन सिंह, संजूबाला, सुमित शर्मा, वेदवीर सिंह आदि उपस्थित रहे।

स्वतंत्रता दिवस को लेकर नोएडा में अलर्ट, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बॉर्डर पर की गई चेकिंग

नोएडा। दिल्ली से सटे होने के चलते नोएडा हमेशा से सेंसिटिव जोन रहा है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस से नोएडा अलर्ट जारी है। साथ ही अलग–अलग जोन में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बॉर्डर पर ये अभियान दिल्ली और नोएडा पुलिस संयुक्त रूप से चला रही है। बॉर्डर पार करने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा संदिग्ध लोगों की आईडी और जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा नोएडा होटल, लॉज व यात्री ठहराव वाले स्थानों के आस–पास चेकिंग की जा रही है। उनके रजिस्टर चेक किए जा रहे है। साथ ही पूरा रिकार्ड भी चेक किया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है। इसके अलावा नोएडा की अंतरराज्यीय व अंत'जनपदीय सीमा चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी बॉर्डर, कालिंदी कुंज बॉर्डर, मॉडल टाउन, लाल कुआं, जेवर सीमा व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे हुए सभी यातायात पॉइंट को चेक करते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया एवं उन्हे आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

बैंक मैनेजर ने सुसाइड किया, पत्नी गिरफ्तार

नोएडा। नोएडा की इको सिटी सोसाइटी में 4 अगस्त को सातवें फ्लोर से गिरकर बैंक मैनेजर ने सुसाइड कर लिया था। इस मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मैनेजर मुंह के बल कॉमन एरिया में लहूलुहान पड़ा हुआ है। मामले में मैनेजर की बहन के आरोप के बाद मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो को पुलिस को भी टैग किया गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। मृतक की बड़ी बहन ने इस मामले में पत्नी के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल नोएडा के सेक्टर–137 स्थित इको सोसाइटी के टावर की 7वीं मंदिर पर स्थित एक फ्लैट में सहिल सबरवाल अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहते थे। एक निजी बैंक में मैनेजर थे। 4 अगस्त को साहिल 7वीं मंजिल से नीचे कूद गए। गंभीर रूप से घायल होने पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया कि घरेलू क्लेश के चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। अक्सर उनकी पत्नी के साथ झगड़ा होता था। अब मृतक की बहन ने पत्नी नेहा अग्रवाल पर साहिल को प्रताड़ित करने और सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए थाना सेक्टर–142 में मुकदमा दर्ज कराया है। इस बीच ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने नेहा अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

पत्रकार से अभद्रता मामले मै कप्तान की कार्यवाही

राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद ने जताया आभार

अवध की आवाज ब्यूरो

मथुरा। थाना राया क्षेत्र में तैनात दरोगा मनोज कुमार द्वारा मीडिया कवरेज के दौरान अभद्रता की जिसकी जानकारी मिलने पर मथुरा जनपद के पत्रकार संगठनों ने अपना विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के आगरा मंडल प्रभारी मनोज कुमार शर्मा और मथुरा संरक्षक दिनेश पंकज और आगरा मंडल उपाध्यक्ष गोपाल चतुर्वेदी सहित मथुरा जनपद के जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह द्वारा दरोगा मनोज कुमार के पत्रकार के साथ किए गए व्यवहार पर भारी विरोध दर्ज कराया और इस मामले मै वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा से मांग की कि इस प्रकार का व्यवहार करने वाले दरोगा को पुलिस लाइन भेजकर जनता और पत्रकारों के साथ बातचीत का लहजा सिखाने के लिए भेजें जिस पर मथुरा के कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों की मांग का सम्मान करते हुए दरोगा मनोज कुमार को लाइन हाजिर कर दिया। पत्रकारों की जायज मांग को मानने पर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के मंडल प्रभारी मनोज कुमार शर्मा और मथुरा संरक्षक दिनेश पंकज, आगरा मंडल उपाध्यक्ष गोपाल चतुर्वेदी, मथुरा जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह, मुकेश गुप्ता, रविकांत चौधरी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को हृदय से आभार व्यक्त किया। इसी प्रकार मथुरा के पत्रकारों के सम्मान की रक्षा करने की आशा व्यक्त की।

राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजि० सुर्खियों में

पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ना संगठन की प्राथमिकता राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के तत्वावधान में फर्रुखाबाद में हुआ पत्रकार सम्मान समारोह राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद हर समय सुर्खियों में रहता है पत्रकारों की आवाज को उठाना संगठन की प्राथमिकता उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में पत्रकार सम्मान समारोह 11 अगस्त को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राजीव भारती जिला अध्यक्ष शिवकांत कटियार एवं जिला प्रभारी गोविंद त्रिवेदी एवम समस्त जिला कमेटी के नेतृत्व में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा साथ में रा0उपाध्यक्ष राकेशधर दुवेदी रा0 सचिव अवनीश कुमार गुप्ता प्रदेश सं0निर्मल कुमार अस्थाना ओम प्रकाश मिश्रा नरेन्द्र वर्मा सहित जनपद की टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माला एवम पगड़ी पहनकर भव्य स्वागत कियागया कार्यक्रम स्थल पर रा0अध्यक्ष जी ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती का पूजन अर्चन किया विभिन्न जनपदों से आए हुए पत्रकारों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फूल माला अंग वस्त्र से स्वागत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रामवीर सिंह नेता जी का एवं कार्यक्रम में आए सभी पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र एवं पटका पहनकर स्वागत किया इसके बाद पत्रकारों ने अपने संबोधन में कहा पत्रकारों के साथ आए दिन हो रही घटनाओं के बारे में बताया वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सैकड़ो की संख्या में आए पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा पत्रकार समाज और शासन के बीच की एक कड़ी होता है पत्रकारों की समस्याओं को देखते हुए हमने राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजि0 संगठन की स्थापना की है जो उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में संगठन कार्य कर रहा है जहां पर पत्रकारों का शोषण होता है उत्पीड़न होता है कोई भी उनकी कलम को दबाने का प्रयास करता है हमारा संगठन उसका विरोध करता है पत्रकार कलम के माध्यम से सच्चाई को लिखना है। उसे कोई भी दबाने का प्रयास करेगा तो हमारा संगठन उसके विरोध में आवाज उठाएगा और हम पत्रकारों के हितों की लड़ाई सदैव लड़ते रहेंगे पत्रकारों के हितैषी कहे जाने वाले देवेंद्र कुमार मिश्रा जी की पत्रकारों के प्रति एक अनूठी शैली रही है किसी भी पत्रकार साथी पर अगर समस्या आती है, तो और रात को 2:00 बजे फोन रिसीव करते हैं और हर संभव समस्या के निस्तारण का प्रयास करते हैं उनका कहना है कि यह पत्रकार रूपी हमारा परिवार है और इस परिवार के सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी प्रथमिकता है उन्होंने कहा अगर किसी भी पत्रकार साथी को हमारे खून के खतरे की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने बदन का एक–एक कतरा पत्रकारों को समर्पित कर दूंगा उन्होंने कहा हम हर राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे केंद्र सरकार से मुलाकात करके पत्रकार सुरक्षा बिल लागू करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें आप लोगों का सहयोग आवश्यक है भारत का एक पहला संगठन है जो पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है श्री मिश्रा ने कहा कि हम संगठन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं पत्रकार सुरक्षा कानून बिल लागू किया जाए पत्रकारों के परिवार को निशुल्क शिक्षा एवं चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए पत्रकारों का 50 लाख का बीमा किया जाए पत्रकारों को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाए पत्रकारों का टोल टैक्स माफ किया जाए पत्रकारों पर बिना जांच के फर्जी मुकदमे ना लिखे जाएं पत्रकारों पर हो रहे हमले में तुरंत आरोपियों को जेल भेजा जाए पत्रकारों को मासिक भत्ता दिया जाए जिस प्रकार एक सरकारी कर्मचारियों के साथ घटना घटने पर उन्हें आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है इस प्रकार अगर किसी पत्रकार साथी के साथ घटना घटती है तो उसे भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए पत्रकारों को पत्रकारों को निशुल्क आवास उपलब्ध कराए जाएं उन्होंने केंद्र सरकार राज्य सरकार से अपील करते हुए कहां की पत्रकारों की समस्याओं को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून बिल लागू करें जिससे हमारा हर पत्रकार साथी अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहते हुए जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक निष्पक्ष रूप से पहुंचने का कार्य करता रहे।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी–97/3 व 7,सेक्टर–7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522–4340954 मो0–7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com
R.N.I.- UPHIN/2012/45127
नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।